Category	Strength as on 1.12.98	Annual Expenditure on salaries and perquisits (Rs. in crores)
Pilots/Co-pilots	440	95.53
Secretarial Staff	1116	48.00

(b) While no category of employees has been identified as excess in Air India the employess to aircraft ratio is higher in comparison with other reputed airlines. Air India is yet to finalise the Voluntary Retirement Scheme.

Appointment of Stores and Supply Assistant in Indian Airlines

2508. SHRI GANDHI AZAD:
SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the names of candidates empanelled in February, 1995 for the post of "Stores and Supply Assistant" in Indian Airlines indicating General/SC/OBC category;

(b) the date of issuance of appointment offer;

(c) the criteria adopted for the offer of appointment;

(d) the names of candidates who declined the appointment offer indicating the date of refusal to accept the offer;

(e) whether the empanelled candidates were given appointment offer according to the merit; and

(f) if so, the details thereoff indicating category-wise (SC/ST/OBC) names of the candidates; if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) No candidates were empanelled in February, 1995 for the post of "Stores and Supply Assistant" in Indian Airlines.

(b) to (f) Do not arise.

औद्योगिकी तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित मामले

2509. **श्री डी०पी० यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण (बी०आई०एफ०आर०) के पास रूग्ण इकाइयों के कुल कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या विभाग इन रुग्ण इकाइयों को बेचने का विचार रखता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालयत (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) से (ग) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के उपबंधों के अन्तर्गत दिनांक 31.10.1998 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास 2381 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां पंजीकृत थीं। इनमें से 1722 मामलों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निपटाया जा चुका है और शेष 659 मामले विभिन्न चरणों में लम्बित हैं। इन एककों को बेचने के बारे में एसआईसीए के उपबंधों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

"फेरा" उल्लंघन के मामले

2510. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्ष-वार और राज्य वार "फेरा" उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) गिरफ्तार किए गए लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इन मामलों में जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) "फेरा" के अन्तर्गत किस प्रकार के दण्ड का प्रावधान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार "फेरा" को संशोधित करने अथवा इसके स्थान पर एक नया अधिनियम लाने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय (वैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) और (ख) महोदय, विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन के मामलों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

	1996		1997		1998 (30.11.1998 तक)	
क्षेत्र	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
अहमदाबाद	*	*	161	04	233	13
बंगलौर	**	**	54	03	103	08
कलकत्ता	263	29	279	11	297	07
चेन्नई	726	47	903	31	509	15
दिल्ली	309	19	307	32	121	08
जलन्धर	170	28	291	23	114	06
मुम्बई	815	100	726	55	426	25

* मुम्बई क्षेत्र के आंकड़ों में शामिल

**चेन्नई क्षेत्र के आंकड़ों में शामिल

अधिकतर मामलों में जहां गिरफ्तारी भी की गई है। जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियम्न अधिनियम दो प्रकार के दंड का प्रावधान करता है। उन मामलों में जहां न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं दोषी पाये गए व्यक्तियों को, उल्लंघन में अन्तर्ग्रस्त रकम के पांच गुणा तक, या 5,000 रुपये जो भी अधिक हो अधिरोपित किया जा सकता है। उन मामलों में जहां अभियोजन कार्रवाई विधि न्यायालय में चलायी जाती है, आरोपित व्यक्तियों को मामलों में अन्तर्ग्रस्त रकम के अनुसार छह माह से लेकर सात वर्ष तक की कैद अथवा जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।

(घ) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को निरस्त करने एवं विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को संशोधित तथा समेकित करने हेतु दिनांक 4 अगस्त, 1998 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक, 1998 लोक-सभा में पेश किया जा चुका है।

ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही

2511. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:
श्री राजा मोहिन्दर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बैंकों को उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर उसे वापिस नहीं करते;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान किस-किस बैंक ने कितनी-कितनी राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्यवाही की;

(ग) क्या इस कानूनी कार्यवाही के फलस्वरूप ऋणों का पुनर्भुगतान किया गया; और